

एक नजर सरयू का जल स्तर घटा, कटान का खतरा बरकरार



—भारतीय बस्ती संवाददाता—
विक्रमजोत (बस्ती)। सरयू नदी का जलस्तर तेजी से कम हो रहा है जिसके चलते बाढ़ प्रभावित गांवों में भरा बाढ़ का पानी नदी की ओर लौट रहा है। बाढ़ के पानी के साथ आयी सील्ट प्रवाह रास्ते और स्कूल कॉम्पस में जमा हो गयी है। गांव में भरे बाढ़ के पानी से जमीनें दलदली हो गयी हैं और जगह जगह पानी जम गया है। वहीं कोहराड़ और पानी भरने से हरी घासां के सड़न व दुर्गंध से बीमारियों का खतरा मंडराने लगा है।

विक्रमजोत क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित गांवों में संकामक रोग की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य टीम आवश्यक टीकाकरण और दवाओं का डिब्बाकरण में फिसड़ती साबित हो रही है। कल्याणपुर के ग्राम ध्यान जैसराज में बताया कि एचएनपीए और आशा के आलावा कोई स्वास्थ्य टीम गांव में झुकने नहीं आयी। विगत वर्ष की भांति पशु पालन विभाग के चिकित्सक गांवों में नदी किनारे बसे कृष्णा नगर टोले में महादलित समाज के घरों को बुखार खात आने के हवाले कर दिया गया था। आरक्षियों में मौके पर फायरिंग की थी।

महादलित परिवार के घरों में लगाई आग: 15 गिरफ्तार



भरना (आम)। विहार के नवादा में महादलित परिवार के घरों को आग के हवाले करने के मामले में 28 नागरिक लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने अब तक 15 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य की तलाश के लिए घुमना जारी है। पुलिस ने नवादा के इस कंडे के मुख्य आरोपी नंदू पासवान को भी पकड़ लिया है। इस कंडे के ज्यादातर आरोपी दलित हैं। बता दें कि मुफ्तसिल इलाका में दोहरे गांव में नदी किनारे बसे कृष्णा नगर टोले में महादलित समाज के घरों को बुखार खात आने के हवाले कर दिया गया था। आरक्षियों में मौके पर फायरिंग की थी।

विहार सरकार में मंत्री रलेश

श्री कृष्णा मिशन हॉस्पिटल में पेशाब की थैली से 60 एम.एम. के पथरी का सफल अपरेशन



—भारतीय बस्ती संवाददाता—
बस्ती। श्री कृष्णा मिशन हॉस्पिटल में सर्जन डा. अमित नायक ने एक मरीज के पेशाब की थैली से 60 एम.एम. के पथरी का सफल अपरेशन किया। डा. नायक ने बताया कि पेशाब की थैली में पथरी के बहुत कम मामलों आते हैं। यदि मरीज का समय से अपरेशन न होता तो वह जानलेवा हो जाता।

बस्ती जनपद के अररुछी निवासी 59 वर्षीय परशुमन को पेशाब

करने से जुड़ा है। घटना बुधवार की रात हुई थी। इसमें 10-12 बकरियों व कुछ मुर्गियों के झुलसने से मौत हो गई। हालांकि घटना में किसी व्यक्ति के घायल होने की खबर नहीं है।
पथिकों का आरोप है कि 30 से अधिक फूस, मिट्टी और कच्चे ईट से बने घरों को फूट दिया गया, जिसमें पीड़ितों के घरों में रखा साग अनाज, कपड़ा, चूल्हा, बर्तन, पंखा, डीजल पंपिंग सेट, रिक्शा, साइकिल आदि साग सामान जलकर राख हो गया। घटना में एक बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई। जिला प्रशासन द्वारा 21 घरों को फूट देने एवं 13 घरों को क्षतिग्रस्त कर दिव्य जांच की पुष्टि की गई है। डीएम आशुतोष कुमार व मां एवं एसीएम अनिल कुमार ने बताया कि घटनास्थल पर मजिस्ट्रेट व पुलिसबलों की तलाक

डा. नवीन उत्पाध्यक्ष, डा. वी.के. वर्मा राष्ट्रीय संयुक्त सचिव बने

—भारतीय बस्ती संवाददाता—
बस्ती। विश्व संवाद परिषद योग एवं प्रगति (विकित्सा प्रकोष्ठ) के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर डा. नवीन सिंह को योग एवं अंतरिक्ष क्षेत्र में राष्ट्रीय महासभा त्रिदेवी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि कुमार राणा और राष्ट्रीय महासचिव अमिषेक सिंह ने दोनों पदाधिकारियों से योग और खेल के क्षेत्र में सहभागिता बढ़ाने का आग्रह किया है।

एनवाईएसडीएफ के राष्ट्रीय रेनू सिंह बनी अखिल भारत हिंदू महासभा की महिला जिलाध्यक्ष

दोनों आयुष्य विकित्स्को को राष्ट्रीय पदाधिकारी बनाए जाने पर योग और खेल से जुड़े अनेक वरिष्ठ जनों ने प्रसन्नता व्यक्त किया है।



—भारतीय बस्ती संवाददाता बस्ती। अखिल भारत हिंदू महासभा त्रिदेवी ने परशुमनपुर ब्लॉक की पथरी बाबू निवासी रेनू सिंह को

फैक्ट्री खोलने का सपना दिखाकर महिलाओं को बनाया टगी का शिकार

—बैंकों की कर्जदार हो चुकी महिलाओं ने डीएम से लागाया न्याय की गुहार

—अखिलेश सिंह ने किया मामले की जांच: दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग



हुई थी, तो उसने रेखा से कहा कि वह एक फैक्ट्री लगाए वाली है जिसमें उसे पैसे बनाने का वादा है। महिलाओं ने रेखा से कहा कि आप अपना आधार कार्ड, बैंकर कार्ड व 10 कोठी सुझे दे दो और उससे जो भी सामान होगा उसमें तुम्हें बराबर का हिस्सा देंगे। दरम्यान की बालों पर अक्षरों करके रेखा ने उसे अपना आधार कार्ड वोटर कार्ड व 10 कोठी दे दिया। एक सप्ताह बाद दीपमाला ने घर आकर उससे पैसा मांगना शुरू पर रेखा का कहना था कि पैसा दीपमाला के साथ उसके महसूली अंशु व रवि भी मौजूद थे। उसके बाद उस तीनों लोग उसे कई बैंकों को ले जाकर लोन निकलवाकर रुपया अपने पास रकड़ लिया। वह रुपयों के बारे में पूछती तो कहती हैं कि उनकी ही फैक्ट्री लागूवोगे, परन्तु अभी तक फैक्ट्री के सम्बन्ध में कुछ नहीं बताया। इसी दौरान बैंक से ऋण की वसूली भी आ गयी। तब रेखा ने दीपमाला से लोन की अदायगी के बारे में कहा तो दीपमाला, अंशु व रवि उपरोक्त ने कहा कि फैक्ट्री का काम नहीं हो पाया और आपका रुपया भी खर्च हो गया है। लोन लेना का रुकना अदा कर दिया जायेगा। परन्तु उक्त लोगों ने लोन का रुपया ने तो उसे वापस देने में ही बैंक को अदा कर दिया। शिकायत करने पर मंत्री-मित्री मिली व जान से मार जमाने की धमकी देते हुए आमादा फौजदारी हो जाते हैं। इस तरह से उन लोगों ने झूठ बोलकर सरल पत्नी संजय, सुनीता पत्नी राजेश, रीता पत्नी रम्यत, इन्द्रावती पत्नी श्रीपति, श्यामिती पत्नी शर बहादुर, बिन्दु पत्नी विजयी, राधा

तिरुपति मंदिर के प्रसाद में फिश आयाल मिलने की पुष्टि



हैदराबाद (आम)। तिरुपति मंदिर के प्रसाद में फिश आयाल मिलने की पुष्टि हुई है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने तिरुपति मंदिर के प्रसाद में घी की जगह जानवरों की चर्बी मिलने का आरोप लगाया था। इसके बाद सैलफ जांच के लिए भेजे गए, अब जांच के बाद रिपोर्ट सामने आई है जिसमें फिश आयाल मिलने की बात कही गई है। बुधवार को सीएम ने पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी पर आरोप लगाया था कि जगन राज में तिरुपति मंदिर के प्रसाद में घी की जगह जानवरों की चर्बी मिलाई गई।

वॉकी-टॉकी, पेजर में विस्फोट से 20 की मौत

बैरुत (आम)। लेबनान में वॉकी-टॉकी और पेजर सहित संचार उपकरणों के फटने से कम से कम 20 लोगों की जान चली गई और 450 से अधिक घायल हो गए। लाजा हमला लेबनान में पेजर सहित विस्फोट में 20 लोगों की मौत और 2,800 से अधिक अन्य के घायल होने के बीच है।

मण्डलायुक्त ने किया विकास कार्य की समीक्षा

—भारतीय बस्ती संवाददाता—
बस्ती। शासन के प्रशासिकाओं के विकास कार्य की समीक्षा करते हुए मण्डलायुक्त अखिलेश सिंह ने मण्डलीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि अपने विभाग से संबंधित योजनाओं में अपेक्षित प्रगति लाते हुए जनपद को ए व श्रेणी में लाया जाय। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि सुनिश्चित कर कि अस्पतालों में मरीजों को किसी भी प्रकार की अनुपेक्षा न हो पाये। बाढ़ कटने से संबंधित निर्देशित किया कि तत्परा के साथ राशनकट समझ से उपलब्ध कराया जाय। जगत दर्शन में प्राप्त शिकायती प्रश्नों को गंभीरता से ध्यान से निस्तारित किया जाय। उन्होंने यह भी कहा कि जनप्रतिनिधियों से प्राप्त शिकायतों को भी समय से निस्तारित करते हुए उनको अवगत कराया जाय। स्वच्छता पखवाड़ा अभियान के संबंध में समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया जाय। उन्होंने यह भी कहा कि कार्ययोजना बनाते हुए इस महाअभियान को सफल बनायें।

वोपाल लगाकर विद्याकर

—भारतीय बस्ती संवाददाता—
बस्ती। हरिया विद्याकर अजय सिंह द्वारा आपका संवक आपके द्वारा अभियान के तहत विभिन्न गांवों में चौपाल लगाकर सरकार की उपलब्धियां जायें जनता को बताने के साथ ही उनकी समस्याएं सुनकर उनके किराकर निराकरण करने का काम लगातार जारी है। उक्त अभियान के तहत मुफ्तसिल के खडहरिया, अररुपुर, बिठूर, रोहदा और सुकरौली पाण्डेय में ग्रामीणों से रुबरु हुए और उनका कुशल श्रेम जाना साथ ही गांव गांव में पोषण पखवाड़ा कार्यक्रम में भी शामिल हुए। चौपाल में कहीं कहीं किसान, दलित, महिला, बुजुर्ग, युवा श्रमजोत हुए जिनसे उनके बुजुर्गों को विद्याकर ने उनकी समस्याओं से अवगत होकर उनका निराकरण किया। विद्याकर ने सरकार की उपलब्धियां जनतां हुए कहा कि आज भारत का नाम दुनिया में शक्तिशाली देश के रूप में उभरा है। गरीब,

वोपाल लगाकर विद्याकर

उत्कर्षण, निराश्रित गोशाला का संरक्षण, शादी अनुदान योजना, निराश्रित महिला शरण, स्वास्थ्य विभाग से संबंधित योजना तथा पशुओं का टीकाकरण आदि योजनाओं की गहन समीक्षा किया।

वोपाल लगाकर विद्याकर

उन्होंने महत्वपूर्ण कार्यों में गुणवत्तापूर्ण व तेजी लाने के लिए विभागों कोडल तथा तकनीकी अधिकारी नामित करने का निर्देशित किया। उन्होंने यह भी कहा कि जनप्रतिनिधियों से प्राप्त शिकायतों को भी समय से निस्तारित करते हुए उनको अवगत कराया जाय। उन्होंने यह भी कहा कि कार्ययोजना बनाते हुए इस महाअभियान को सफल बनायें।

वोपाल लगाकर विद्याकर

उन्होंने यह भी कहा कि जनप्रतिनिधियों से प्राप्त शिकायतों को भी समय से निस्तारित करते हुए उनको अवगत कराया जाय। उन्होंने यह भी कहा कि कार्ययोजना बनाते हुए इस महाअभियान को सफल बनायें।

चिन्हित किये जा रहे हैं ब्लेक स्पॉट

—भारतीय बस्ती संवाददाता—
बस्ती। स्वच्छता जिले से 1185 ग्राम पंचायतों के सम्बन्ध 213 ग्राम पंचायतों ब्लेक स्पॉट चिन्हित किया जा रहा है। लगभग 500 राजस्व गांवों में सफाई कमी, ग्राम पंचायत सचिव, फौजदार सचिव, एडीओ (पंचायत व अन्य अधिकारी यह देखने निकले हैं कि वह कौन सी जगह है, जहां पर आमतौर पर लोग कूड़ा फेंकने का कारण क्या है। उसकी पहचान की जाएगी। इसके बाद विलिंक ब्लेक स्पॉट की सफाई होगी। इसमें अग्रदानी भी करवाया जाएगा। भीष्म में ब्लेक स्पॉट नहीं बने, इसके लिए भी उपय

विचारित किये जा रहे हैं ब्लेक स्पॉट

—भारतीय बस्ती संवाददाता—
बस्ती। स्वच्छता जिले से 1185 ग्राम पंचायतों के सम्बन्ध 213 ग्राम पंचायतों ब्लेक स्पॉट चिन्हित किया जा रहा है। लगभग 500 राजस्व गांवों में सफाई कमी, ग्राम पंचायत सचिव, फौजदार सचिव, एडीओ (पंचायत व अन्य अधिकारी यह देखने निकले हैं कि वह कौन सी जगह है, जहां पर आमतौर पर लोग कूड़ा फेंकने का कारण क्या है। उसकी पहचान की जाएगी। इसके बाद विलिंक ब्लेक स्पॉट की सफाई होगी। इसमें अग्रदानी भी करवाया जाएगा। भीष्म में ब्लेक स्पॉट नहीं बने, इसके लिए भी उपय



इस अवसर पर रामचंद्र तिवारी, राज दत्त श्रुवाल, राम प्रताप पाण्डेय, आशुतोष सिंह ओटे, सुरेश बुधाला, वीर कुश, विष्णु सिंह, हरे सिंह, मनीष सिंह, भरत सिंह, लवकुश वर्मा, पृथ्वी मौर्य, अशोक सिंह, सुभा, रामनिवास सिंह, सीताराम यादव, अतित निशि, फंका बुधाल, रामयन यादव, अशिलेश चौधरी, अजय चौधरी, परमहंस चौधरी, अरविंद चौधरी, बुध कुमार चौधरी, राम प्रसाद यादव आदि उपस्थित रहे।

"युद्ध अखबार निकालने दो तो मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का नियामक है और कौन कानून का निर्माता" -वेदेल फिलिप्स

दैनिक भारतीय बस्ती

बस्ती 20 सितम्बर 2024 शुक्रवार

सम्पादकीय

पेजर धमाकों का खतरा

लेबनान व सीरिया में एक साथ हुए पेजर धमाकों ने इन देशों को ही नहीं, पूरी दुनिया को चौंकाया। लोगों को समझने में देर लगी आजकल उन्नत मोबाइल फ़ोनों के दौर में पेजर का इस्तेमाल? दरअसल, तकनीकी तौर पर बेहद उन्नत इस्त्राइली फ़ौज व दुनिया में तहलका मचाने वाली खुफिया एजेंसी मोसाद मोबाइल के जरिये अपने कट्टर दुश्मनों को निशाना बनाने लड़े हैं। इसी वजह से ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के रहस्येक अफ़ी रिश्ता गोपीन्य रखने के मकसद से पेजरों का इस्तेमाल सूचना संकेतों के लिये करते रहे हैं। बहरहाल पेजर धमाकों की शृंखला में लेबनान में नौ लोगों के मरने व पौने तीन हजार लोगों के घायल होने की बात कही जा रही है। लेकिन वास्तविक संख्या इससे अधिक हो सकती है। वहीं सीरिया में पत्र धमाकों की शृंखला देखी गई। बहरहाल, हालिया घटनाक्रम इस्त्राइल-हिजबुल्लाह संघर्ष के चिंताजनक स्थिति में पहुंचने का संकेत देता है। युद्ध में इस तरह की रणनीति का पहली बार दुनिया के सामने खुलासा हुआ है, जिसमें अपने विरोधी देश के संचार उपकरणों को निशाना बनाकर हमला किया गया हो। जो इस क्षेत्र में लंबे समय से जारी संघर्ष में परिष्कृत नई रणनीति को ही दर्शाता है। वहीं हिजबुल्लाह की सुरक्षा पर कर्मचारियों को भी उजागर करता है। निरसंदेह, हिजबुल्लाह ईरान समर्थित लेबनान की एक प्रमुख ताकत है, जो उन्नत इस्त्राइली ट्रेकिंग सिस्टम से बचने के लिये अपेक्षाकृत कम उन्नत तकनीक वाले उपकरण पेजर पर निर्भर रहा है। यही वजह है कि हिजबुल्लाह लड़ाकों, चिकित्सकों तथा नागरिकों द्वारा प्रयोग किये जाने वाले पेजर बेरूत के दक्षिणी उपनगरों व बेका घाटी सहित लेबनान के कई गढ़ों में एक साथ फट गए। अस्पताल की तरफ भागती सैकड़ों एंबुलेंसों से पूरे लेबनान में भय व असुरक्षा का माहौल बन गया। यहां तक कि सीरिया के कुछ हिस्सों में भी धमाकों की गूँज सुनायी दी, वहां भी हिजबुल्लाह के लड़ाके इससे प्रभावित हुए।

बहरहाल, लेबनान व सीरिया में पेजर धमाकों की शृंखला पूरी दुनिया को कई सवाल देती है कि संकटकाल में अपने संचार नेटवर्क को बाहरी हस्तक्षेप से बचाने के लिये बहुत कुछ किया जाना जरूरी है। विज्ञान व तकनीकी उन्नत ने युद्धों का पूरा स्वरूप ही बदल दिया है। परंपरागत सेना व सुरक्षा की सारी अमेदा दीवारें तकनीक के हमलों के आगे बेकार साबित हो रही हैं। बहरहाल, इन हमलों के लिये, इस्त्राइली खुफिया एजेंसी पर साजिश करने के आरोप लग रहे हैं। हालांकि, इस्त्राइल ने इन धमाकों को लेकर कोई दावा नहीं किया है, लेकिन रिपोर्ट बता रही हैं कि निर्माण प्रक्रिया के दौरान पेजर से छेड़छाड़ करके उन्हें धमाकों के मकसद से ज्वलनशील बनाया गया है। जो एक बड़े सुनिश्चित ऑपरेशन की ओर संकेत करता है। जिसमें दूर से सुनिश्चित तरीके से विस्फोटकों को अंजाम दिया गया। इस्त्राइल ने इन धमाकों के जरिये हिजबुल्लाह को यह संदेश देने का प्रयास किया है कि भले ही वह गाजा संघर्ष में उलझा हुआ है, इसके बावजूद वह दूसरे मोर्चे पर हिजबुल्लाह के बुनियादी ढांचे को भी निशाना बनाने की क्षमता रखता है। बहरहाल, यह घटना बताती है कि इस्त्राइल पर बीते साल हमला द्वारा किए गए हमले व अपहरण की वारदातों के बाद शुरू हुए टकराव का विस्तार होने की आशंका बलवती हुई है। इस्त्राइल इस समय न केवल हमला बलिवुल्लाह व हूती विद्रोहियों के हमलों का एकसाथ निजाम दे रहा है। लेकिन इस्त्राइल की सीमा से लगते लेबनान में ईरान द्वारा दी गई उन्नत मिसाइलों व रॉकेटों के लगातार हो रहे हमलों के बीच इस टकराव के विस्तार लेने की आशंका बड़ गई है। अब पेजर धमाकों के बाद हिजबुल्लाह इस्त्राइल से बदला लेने की बात कर रहा है, जिससे इस संघर्ष के व्यापक रूप लेने के आसार बढ़ गये। पश्चिम एशिया में पहले से ही नाजुक स्थिति जो गाजा संघर्ष के कारण और जटिल हो गई थी, उसे पेजर प्रकरण ने और गंभीर स्थिति में पहुंचा दिया। बहरहाल, हालिया घटनाक्रम युद्ध के हथियार का रूप में प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोग को दर्शाता है।

महिला अपराध, कानून और समाज

— योगेन्द्र योगी —

देश के नेताओं ने समस्याओं का आसान रास्ता तलाश कर रखा है। जब भी किसी समस्या से सामना हो तो कानून बना कर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लें। समस्या को जड़ तक कोई भी राजनीतिक दल और सरकार नहीं जाना चाहती। ऐसा नहीं है कि समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं हो सकता, किन्तु वहां तक पहुंचने और व्यवहारिक समाधान ढूँढने में पापड़ बेलने पड़ते हैं। पश्चिमी बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार ने महिला चिकित्सक से बलात्कार के बाद हत्या के मामले में बही किया है जो अब तक ऐसे मामलों में दूसरे राज्य या केंद्र सरकार करती रही हैं। मसलन कानून बना कर जिम्मेदारी पूरी कर ली। ममता सरकार ने विधानसभा में बलात्कार रोधी विधेयक सर्वसम्मति से पारित कर दिया। विधेयक के मसौदे में बलात्कार पीडिता की मौत होने या उसके स्थायी रूप से अचेत अवस्था में चले जाने की सूत्र में ऐसे दोषियों के लिए मृत्युदंड के प्रावधान का प्रस्ताव किया गया है। इसके अलावा मसौदे में प्रस्ताव किया गया है कि बलात्कार और सामूहिक बलात्कार के दोषी व्यक्तियों को आजीवन कारावास या सजा दी जाए, और उन्हें पेरेंट की सुविधा भी दी जाए।



राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए जाएगा। इससे पहले 2019 में आंध्र प्रदेश विधान विधेयक और 2020 में महाराष्ट्र शक्ति विधेयक विधानसभा से पारित हुआ था। इन दोनों विधेयकों में बलात्कार और सामूहिक बलात्कार के सभी तरह के मामलों में अनिवार्य फांसी का प्रावधान किया गया था। इन दोनों विधेयकों को राज्य विधानसभाओं ने सर्वसम्मति से पारित किया था। लेकिन इन दोनों विधेयकों अभी तक राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिली है। भारतीय न्याय सिंहात (वीएनएस) और भारतीय नागरिक फांसी के साथ-साथ 2012 के पोस्को अधिनियम के कुछ हिस्सों में संशोधन करने और पीडिता की उम्र चारह जो हो, कई तरह के यौन उल्टीजन के मामलों में मौत की सजा का प्रावधान है। इस बिल में महिलाओं और बच्चों के साथ होने

वाले अपराध के लिए कठोर सजा का प्रावधान किया गया है। बीते महीने लागू हुए वीएनएस की धारा-64 में बलात्कार के लिए 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। वहीं वीएनएस की धारा-66 में बलात्कार और हत्या और ऐसे बलात्कार, जिनमें पीडितिका नष्ट हो जाती है, उनमें मौत की सजा का प्रावधान है। इसमें 20 साल की जेल की या उस केंद्र की सजा का भी प्रावधान किया गया है।

गौरतलब है कि निर्भया कांड के बाद कानून को बहुत सख्त कर दिया गया था। रैप की परिभाषा भी बदल दी थी, ताकि महिलाओं के खिलाफ अपराध में कमी लाई जा सके। पहले जबरदस्ती या असममति से बनाए गए संबंधों को ही रैप के दायरे में लाया जाता था। लेकिन इसके बाद 2013 में कानून में संशोधन कर इसका दायरा बढ़ाया गया। इतना ही नहीं, जुवेनाइज कानून में संशोधन किया गया था। इसके बाद अगर कोई 16 साल और 18 साल से कम उम्र का कोई किशोर जघन्य अपराध करता है तो उसके साथ वयस्क की तरह ही बर्ताव किया जाएगा। हालांकि, इन सबके बावजूद सुधार नहीं हुआ है।

दफनाया गया। मध्य प्रदेश के मुर्ना जिले में एक महिला के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना सामने आई। पीडिता की शिकायत के बावजूद, पुलिस ने समय पर कार्रवाई नहीं की, जिससे व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए। हैदराबाद में एक महिला वेटनररी डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या की घटना ने व्यापक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया। अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने कार्रवाई की, और बाद में आरोपी एनकाउंटर में मारे गए, जिसने विवाद और बहस को जन्म दिया। मणिपुर में एक महिला के साथ बलात्कार और हत्या की घटना ने हाल ही में बहुत ध्यान खींचा। इस मामले ने स्थानीय हिंसा और सामाजिक अस्थिरता को भी उजागर किया। साल 2013 में केंद्र सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए नित्या फंड बनाया, जिसका मकसद राष्ट्यों को महिलाओं की सुरक्षा को पुष्टा करना था। मगर, इसका अभी पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं हो पाया है। नित्या फंड की 9 हजार करोड़ रुपये की धनराशि का लगभग 30 प्रतिशत हिस्सा भी सही से इस्तेमाल नहीं हो पाया है। निर्भया फंड बनने से लेकर 2021-22 तक, कोष के तहत कुल आवंटन 6,000 करोड़ रुपये से ज्यादा रहा है, जिसमें से 4,200 करोड़ रुपये का ही अब तक इस्तेमाल हो पाया है।

बुलडोजर न्याय और राजनीति

—रोहित कौशिक—

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक मामलों में अभियुक्त की संपत्ति को ध्वस्त करने के लिए बुलडोजर के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के.बी. विश्वनाथन की पीठ ने आदेश दिया कि सुनवाई की आगामी तारीख 1 अक्टूबर तक कोर्ट की अनुमति के बिना कोई लोककोड नहीं की जाएगी। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश सड़कों, फुटपाथों, खेतों लाइनों व जलाशयों के अतिक्रमण पर लागू नहीं होगा। शीर्ष न्यायालय ने अर्द्ध 1 तरीके से की कई एसी कार्रवाइयों को संभावित के मुल्यों के विरुद्ध माना है। पिछले दिनों बुलडोजर के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के बीच हुई बहस ने योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि बुलडोजर वही व्यक्ति चला सकता है, जिसमें बुलडोजर चलाने की क्षमता हो।



बुलडोजर चलाने के लिए दिल्, दिमाग और हिम्मत की जरूरत होती है। रंगडायो के सामने नारा राइजने वाले या बुलडोजर चलाएंगे? समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा था कि माजना सरकार में निंदीय लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं। किसान परेशान हैं और नौजवानों का भविष्य अंधकार में है। 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही पूरे प्रदेश का बुलडोजर मोखपुर की ओर मुड़ जाएगा। कुछ समय पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने यह वादा उठाया था कि क्या किसी का मकान सिर्फ इंसलिए गिराया जा सकता है कि वह एक आरोपी है? सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि वह किसी भी अनधिकृत निर्माण या सार्वजनिक सड़कों पर अतिक्रमण को रोकना नहीं देगा। कुछ वर्षों से बुलडोजर को अपराधियों के खिलाफ जैसे टैलरस पॉलिसे के तहत प्रतिक के तौर पर प्रस्तुत किए गए का प्रचलन बढ़ रहा था।

सरकारों के इस व्यवहार पर कई तरह के बवाल उठ रहे थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलवाना शुरू किया था। इस कदम से एक विचारधारा के लोगों में योगी आदित्यनाथ काकी लोकप्रिय हुए और उन्हें बुलडोजर

सवाल यह है कि जब व्यक्ति को किसी अपराध का आरोपी घोषित किया जाता है, तभी उसके अवैध निर्माण का पता क्यों चलता है। सवाल यह भी है कि सत्ता पक्ष के कितने लोगों पर बुलडोजर चलाया गया है? जब एक राजनीति के तहत बुलडोजर चलाया जाएगा तो उस पर सवाल उठेंगे ही। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह वायदा किया था कि उत्तर प्रदेश में भू-माफियाओं को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। बुलडोजर न्याय इसलिए किया असंवैधानिक है क्योंकि जब घर को ध्वस्त किया जाता है तो उससे परिवार के वे लोग भी प्रभावित होते हैं, जिनकी कोई गलती नहीं होती है।

समुदाय को निशाना बनाने का विरोध किया था। इसके अतिरिक्त भी सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर न्याय के खिलाफ अनैक याचिकाएं दायर की गई थीं। काकी लोग अपराधियों के खाने के लिए बुलडोजर न्याय को सही उधारते हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब बुलडोजर से ही न्याय देना है तो देश में न्यायालय का क्या काम है? संविधान विशेषज्ञों का भी मानना है कि बुलडोजर न्याय संविधान समत नहीं है। आपत्तियों को फलफट दोषी घोषित कर देना और न्यायालय को नकार कर स्वयं ही बुलडोजर चलवाना भला संविधान समत कैसे हो सकता है? कट्टर सत्य तो यह है कि अधिकांश मामलों में बुलडोजर एक ही धर्म के लोगों के खिलाफ चलाया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि राज्य में किसी का भी घर दिना कानूनी प्रक्रिया के नहीं तोड़ा जा रहा है।

—विपिन पब्ली—

राष्ट्रीय जनगणना में हो रही अनवश्यक देरी पर लंबी सुप्री कोर्ट ब्याद, केंद्रीय गृह मंत्री अनित शाह ने बयान दिया है कि जनगणना की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी। उन्होंने तो देश के बारे में बताने की जहमत उठाई है और न ही कोई निश्चित समय-सीमा बताई है जिसके दौरान यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। विशेष रूप से, जुलाई में पेश किए गए बजट में जनगणना करण के लिए बहुत काम प्राधान्य था। 2024-25 के बजट में जनगणना और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एन.पी.आर) की तैयारी के लिए 1,309 करोड़ रुपए का मान्यती परिषय प्रदान किया गया, जबकि 2019 में केंबिन्ट द्वारा प्रस्तावित 2021 की जनसंख्या के लिए 12,700 करोड़ रुपए के ब्यय को मंजूरी दी गई थी। इस बार कम प्राधान्य के कारण 2020 कोविड महामारी के कारण सरकार के लिए बहुत काम प्राधान्य के शुरू होने की संभावना बहुत कम रह गई है। वास्तविक सच जनगणना से पहले बहुत सारे काम किए जाने की जरूरत है, लेकिन इस दिशा में कोई प्रयास किए जाने के संकेत नहीं है। नदीनमन आंकड़े उपलब्ध न होने के कारण, सभी सरकारी नीतियां और कल्याणकारी योजनाएं 14 साल पुराने आंकड़ों पर आधारित हैं।

आंकड़ों की अनुपलब्धता ने कई मिथकों को जन्म दिया है और विभिन्न समुदायों की जनसंख्या और विकास दर के बारे में झिंकू कथा को जन्म दिया है, जो एक विश्वकी पीढ़ी के हित में है। 2021 में देशकी जनगणना के स्वगन के बाद से, सरकार जनगणना को रोकने के लिए अतिरिक्त नितियां बहुत खर्च हो चुकी हैं। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि 1881 में शुरू की गई इस श्रृंखला के बाद से हर 10 साल में विना किसी रुकावट या देरी के जनगणना की जा रही है। स्वतंत्रता के बाद पहली जनगणना भी 1951 में तय

जगनगणना में देरी क्यों...?

कार्यक्रम के अनुसार की गई थी। किसी देश के विकास, नियोजन और नीति-निर्माण के लिए जनगणना बहुत महत्वपूर्ण है। यह जनसंख्या की सटीक गणना प्रदान करती है, जिससे सरकारों को जनसांख्यिकीय रूझान, आर्य वितरण और जनसंख्या वृद्धि को समझने में मदद मिलती है। बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सामाजिक सेवाओं के लिए धन जैसे संसाधनों का आवंटन जनगणना के आंकड़ों पर निर्भर करता है। जनगणना के आंकड़े आर्थिक विकास के क्षेत्रों की पहचान करने, व्यावसायिक निवेश नियंत्रण करने और मज बाजार की गतिशीलता को समझने में मदद करते हैं। इसके अलावा यह राशरी और अभाव वाले क्षेत्रों की पहचान करने, स्वास्थ्य सेवा और स्वच्छता जैसे बुनियादी सेवाओं तक पहुंच जैसी सामाजिक कल्याण गतिविधियों को उजाहरण करने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, अगर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की कवरज को संशोधित करने के लिए अद्यतन जनसंख्या के आंकड़े उपलब्ध होते, तो सबसिडी वाले खाद्य राशन के लाभार्थियों की संख्या में 100 मिलियन से अधिक की वृद्धि होने का अनुमान है।

आवास और शहरी शिक्षा, बिजली और पानी जैसी उपयोगिता सेवाओं और परिवहन प्रणालियों का विकास करने के लिए डाटा मार्गदर्शन किया है। इस प्रकार यह सूचित निर्णय लेने में मदद करता है। जनगणना में देरी और लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के सीमांकन बच-बच श्रॉन के कारण स्थिति पैदा हो गई है कि निर्वाचन निर्वाचन क्षेत्र 1971 में 315 एफ 50 साल से अधिक पुराने आंकड़ों पर आधारित हैं। एक राय यह है कि सार्वजनिक पार्टी जनगणना जनगणना में देरी कर रही है क्योंकि वह 2029 के लोकसभा चुनावों की प्रत्याशा है 'परीसीमन' अन्याय को ठीक करना चाहती है। संविधान के 84वें संशोधन में कहा गया है कि अन्तर्गत परसीमन अन्याय 2026 के बाद पहली जनगणना पर आधारित हो जाएगा।

सीएम योगी ने अयोध्या को दी 1004 करोड़ की सौगातें, बोले-सपा दुनिया की सबसे बड़ी माफिया पार्टी



यूपी के सीएम योगी ने अयोध्या को 1004 करोड़ की सौगातें दीं। मिल्कीयत के विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में 83 करोड़ की 37 योजनाओं का लॉकरागण किया है।

यूपी के सीएम योगी ने अयोध्या को 1004 करोड़ की सौगातें दीं। मिल्कीयत के विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में 83 करोड़ की 37 योजनाओं का लॉकरागण किया है।

कमरा बंद कर फांसी के फंदे से लटकी महिला, मौत

पीठा लेकिन चुनाव नहीं। मुनका के देवर मुसुवर ने 112 नंबर पर फोन कर सूचना दी तो पुलिस मौकें पर पहुंच गई।

मौत का कारण नहीं। मुनका के देवर मुसुवर ने 112 नंबर पर फोन कर सूचना दी तो पुलिस मौकें पर पहुंच गई।

सीएम योगी ने कार्यकर्ताओं को दिया मंत्र, बूथ



यूपी के सीएम योगी ने अयोध्या को 1004 करोड़ की सौगातें दीं। मिल्कीयत के विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में 83 करोड़ की 37 योजनाओं का लॉकरागण किया है।

यूपी के सीएम योगी ने अयोध्या को 1004 करोड़ की सौगातें दीं। मिल्कीयत के विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में 83 करोड़ की 37 योजनाओं का लॉकरागण किया है।

दूसरे की जगह पर खड़ा होकर कर दिया था बैनामा, गिरफ्तार

संत कबीर नगर जिले के मंडलादल तहसील के क्षेत्र में 25 वर्ष से यावद व्यक्ति की जगह अपने आपको दिखा कर भूमि का बैनामा कराने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।

संत कबीर नगर जिले के मंडलादल तहसील के क्षेत्र में 25 वर्ष से यावद व्यक्ति की जगह अपने आपको दिखा कर भूमि का बैनामा कराने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।

किसानों की समस्याओं को लेकर प्रशासन पर बरसी भाकियू

संत कबीर नगर जिले के मंडलादल तहसील के क्षेत्र में 25 वर्ष से यावद व्यक्ति की जगह अपने आपको दिखा कर भूमि का बैनामा कराने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।

संत कबीर नगर जिले के मंडलादल तहसील के क्षेत्र में 25 वर्ष से यावद व्यक्ति की जगह अपने आपको दिखा कर भूमि का बैनामा कराने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।

युवती की शादी कहीं और तय हुई तो कार से कुचलकर मार डाला



यूपी के सीएम योगी ने अयोध्या को 1004 करोड़ की सौगातें दीं। मिल्कीयत के विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में 83 करोड़ की 37 योजनाओं का लॉकरागण किया है।

यूपी के सीएम योगी ने अयोध्या को 1004 करोड़ की सौगातें दीं। मिल्कीयत के विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में 83 करोड़ की 37 योजनाओं का लॉकरागण किया है।

चबूतरा ऊंचा करा रहे व्यक्ति को दरोगा और सिपाही ने पीटा, निलम्बित

ग्रामीण शाह हुए इसके बाद पुलिस के मौजूदगी में पूजा स्थल का चबूतरा ऊंचा किया गया।

पंचायत भवन के गुणवत्ता विहीन निर्माण का आरोप: डीएम से किया शिकायत

रंजु अली को हिरासत में लेकर पुलिस के मौजूदगी में पूजा स्थल का चबूतरा ऊंचा किया गया।

भारतीय बस्ती संवाददाता-सिद्धार्थनगर (जैगियू) विकास

संवाददाता-सिद्धार्थनगर (जैगियू) विकास... आदालती नोटिस... अदालती नोटिस...

अदालती नोटिस

अदालती नोटिस... अदालती नोटिस... अदालती नोटिस...

अदालती नोटिस

अदालती नोटिस... अदालती नोटिस... अदालती नोटिस...

अदालती नोटिस

अदालती नोटिस... अदालती नोटिस... अदालती नोटिस...

अदालती नोटिस

अदालती नोटिस... अदालती नोटिस... अदालती नोटिस...

खण्ड जाँगीया के नवदालिया ग्राम के ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को शिकायत पत्र देकर पंचायत भवन के घटिया निर्माण की जांच करने की मांग किया।